

कलम ने रोटी छीन ली  
अनिश्चित कालीन धरना 3ए अक्टुबर 2006 से, जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़.

सरकार ने अभी सितम्बर 2006 में पुराने बी.पी.एल. चयनित परिवारों की सूची को समाप्त करके नयी सूची निकाली है। इस बार पूरे जिले में 77 हजार 111 परिवारों के नाम चयनित सूची से हटा दिया है। भदोसर तहसील की ग्राम पंचायत पोटरों के गांवों में भील जाति के 70 परिवार हैं। जिनके रहने के लिए टूटे फुटे झोंपड़े हैं, खेति के लिए जमीनें नहीं हैं, अधिकतर युवक बंधुआ मजदूर (हाली) रहे या वर्तमान में हैं। वे परिवार के लिए मुश्किल से खाने का अनाज खरीद पाते हैं। इलाज के नाम पर तो उन्हें मरना ही पड़ता है। इसी प्रकार अन्य जातियों में भी बहुत से गरीब, विधवाएँ, निःशक्त परिवार हैं जिनका जीवन अनाज नहीं मिलने और बिमारी का इलाज नहीं होने से कष्ट में है, परन्तु सरकार द्वारा सर्वे करवाकर बनायी नयी बी.पी.एल. सूची में इन सब परिवारों को अमीर और साधन-सम्पन्न बताकर बी. पी. एल. चयनित का हक भी छीन लिया है।

यह स्थिति मात्र पोटरों ग्राम पंचायत के गांवों की ही नहीं जिले कि हर ग्राम पंचायतों के कई गांवों की यही कहानी है। इसके लिए जिम्मेदार यह सर्वे करवाने वाला सरकारी महकमा है, जिसमें ऐसे लोग जिनको गांव के गरीबों के बारे कुछ भी जानकारी नहीं थी। सर्वे के 13 प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे थे कि दोनों समय भोजन मिलता है या नहीं, कपड़े कितने पहनते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, कर्ज का प्रकार, बाहर मजदूरी करने जाते या नहीं (निष्क्रमण), परिवार में मजदूरी की स्थिति और सहायता हेतु मांगना। ये ऐसे अस्पष्ट प्रश्न हैं जो वास्तविक गरीब परिवार की पहचान को भटकाने वाले हैं।

यह सर्वे का कार्यक्रम जब सन् 2002 में शुरू हुआ तभी से ही जन संगठनों ने सर्वे के ऐसे प्रश्नों का तिव्र विरोध किया परन्तु सरकार ने अपनी जिद पर अड़कर पूरी लापरवाही से सर्वे करवाया। सर्वे के बाद वार्ड सभाओं और ग्राम सभाओं में भी सरकारी अधिकारियों ने तानाशाही की और जनता को गुमराह करके गैरजिम्मेदारी से गरीबों की रोटी छीनने की पूरी तैयारी करली।

तब जाकर पूरे चित्तौड़गढ़ जिले कि तहसील मुख्यालयों पर 7 हजार 655 परिवारों के व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर पुनः सर्वे के लिए अपील दर्ज की जिसे सरकारी अधिकारियों ने लापरवाही से अनसुना कर दिया। ऐसे समय में राजनीतिक पार्टियों के नेता और जनप्रतिनिधि भी प्रशासनिक अधिकारियों के पक्ष में चुप थे। अब सुचियों तैयार होकर ग्राम पंचायतों में पहुँच गयी हैं जिसमें ग्राम पंचायतों के कई गांवों में सारे गरीब परिवारों के नाम चयनित सूची से कट गये हैं या बहुत कम लोगों के ही नाम आये हैं जिससे गांवों के गरीब लोगों में तिव्र आक्रोश होने के कारण विरोध कर रहे हैं। तब जाकर गांवों में पंच-सरपंच और अन्य जन प्रतिनिधि अलग-अलग विरोध करके आन्दोलन कर रहे हैं। जिससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब इस असंवेदनशील, बेरहम सरकार के कान खोलने के लिए गांव-गांव से जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक जुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके विरोध में जन संगठनों ने जिला मुख्यालय पर 3. अक्टुम्बर से अनिश्चित कालीन धरना रखा है।

अपने हक के लिए आवाज उठाओं और धरने में शामिल हो। गांव और शहर के जिन प्रबुद्ध नागरिकों को लगता है कि बरीबों के साथ यह अन्याय हुआ है वे अपना सहयोग और समर्थन

खेतिहर खान मजदूर संगठन (राजस)

चित्तौड़गढ़  
फोन नः 01472-243788

मजदूर किसान संगठन

अमरपुरा, त. भदोसर, जि. चित्तौड़गढ़  
मो. न. 9414777962